HARYANA GOVERNMENT
AGRICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION

Chandigarh Dated 5-2-16

No. 5934-Agri-II (1)-2015/1480 -.The Governor of Haryana is pleased to constitute a State Project Management Unit (SPMU) to achieve the objectives as directed within the NeGP-A project guidelines, with following composition:-

1. Nodal Officer Agriculture – JD (Admn.)
2. Nodal Officer Fisheries – DD (Planning)
3. Nodal Officer Horticulture – JD (Horticulture)
4. Nodal Officer from NIC–Sector coordinator NIC, Agriculture Department.
5. Nodal Officer from Hartron–GM (Hartron)
6. Accounts Officer (HQ) Agriculture Department

Key activities to be undertaken by the State Government:-

i) State Agriculture Department to be Nodal Department.

ii) Civil Infrastructure Preparation (including provision of space for Help Desk and, if any component of a Service is to be developed in the State, for the outsourced programmers).

iii) Planning, procurement, distribution, installation and accounting of complete hardware.

iv) Backup power arrangements, wherever needed.

v) Hiring of manpower on contract basis.

vi) Setting up of State Project Monitoring Unit (SPMU).

vii) Comprehensive inputs on SRS documents and feedback on pilot run of software packages.

viii) Infrastructure and logistic related support to NIC for training and capacity building.

ix) Data digitization, localization (including translation of web-pages in language of the State) and updation of data regularly by various stakeholders in the State.

x) Receipt and Acceptance Testing of the computer hardware and system software.

xi) Recurring expenditure on power and consumables except to the extent of funding by the Government of India.

xii) The States will need to give its share only for manpower (0%, 30% & 50% State share during first 3 years after which Government of India support on manpower will cease) and contribute to site preparation (45% State share except sites for the Training Centres which will be funded fully by the GOI).

xiii) Senior nodal officer for interacting with GOI and other Stakeholders.

xiv) Help Desk – State (with vernacular language Support)

xv) Training - Top officials at the State level from all the participating States and resources from their field level attached offices. Additionally, representatives from the State Agricultural University.

The officers at the District level, who are primarily responsible for implementing the project at the District level and would be required at the front end for service delivery, would be trained accordingly.

Employees who will also act as trainers responsible for training of lower officials, transferred or new officials and conducting refresher courses. The training of VLEs at CSCs shall also be organised at District level to enable them for implementing NeGP-A initiatives.

State will actively involve CSCs in implementing the G2C services effectively. Expenditure on this account will be borne out of item A2 in the Cafeteria of Activities under ATMA Scheme. Such a training will be provided at least twice during 12th Plan period by restricting the expenditure @ Rs. 400 per day (plus lodging charges if any) by treating them as para extension workers.

Officials who will be involved in day-to-day activities at the ground level alongwith various resources at the Block/Mandal and village levels, would be directly interfacing with the end beneficiaries on a day-to-day basis and would be required to facilitate the service delivery. These stakeholders would also require to be trained in all the aspects of service delivery as they would be representing the Agriculture MMP to the farmers and businesses at the village level."

VARINDER SINGH KUNDU,
Addition Chief Secretary to Govt. of Haryana
Agriculture Department.

Endst. No. 5934-Agri-II (1)-2015/1481 Chandigarh Dated 5-2-16

A copy is forwarded to Controller Printing and Stationary, Haryana. He is requested to publish the above notification in the Gazette (extra ordinary) of Haryana.

Under Secretary,
for Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
Agriculture Department.

Endst. No. 5934-Agri-II (1)-2015/1482 Chandigarh Dated 5-2-16

A copy is forwarded in the Secretary Agriculture, Govt. of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi for information.

Under Secretary,
for Addition Chief Secretary to Govt. of Haryana
Agriculture Depaerment.

Endst. No. 5934-Agri-II (1)-2015/1483 Chandigarh Dated 5-2-16

A copy is forwarded to the Director Agriculture, Haryana, Panchkula for information and necessary action. He is requested that copies of the notification may please be send to concerned quarters at his own level.

Under Secretary,
for Addition Chief Secretary to Govt. of Haryana
Agriculture Department.

हरियाणा सरकार
कृषि विभाग
अधिसूचना

चण्डीगढ दिनांक 05/02/16

क्रमांक 5934--कृषि--II (1)--2015/1472 हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित संरचना के साथ राज्य में राष्ट्रीय ई--शासन योजना--कृषि के कियान्वयन के लिए सहर्ष राज्य अधिकारप्राप्त समिति का गठन करते है;--

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव हरियाणा सरकार कृषि विभाग	अध्यक्ष
2. सचिव/महानिदेशक (सूचना प्रोधौगिकी)	सदस्य
3. महानिदेशक (बागवानी)	सदस्य
4. महानिदेशक (पशुपालन)	सदस्य
5. निदेशक (मत्स्य पालन)	सदस्य
6. सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
7. राज्य ई--शासन मिशन दल के प्रतिनिधि	सदस्य
8. राज्य सूचना अधिकारी	सदस्य
9. परियोजना ई--शासन मिशन दल के प्रतिनिधि	सदस्य
10. आई0एम0डी0 के प्रतिनिधि	सदस्य
11. राज्य कृषि विश्व विद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि	सदस्य
12. निदेशक कृषि हरियाणा पंचकुला	सदस्य सचिव

राज्य अधिकार प्राप्त समिति की भूमिकाएं एंवम जिम्मेदारीयां

1. परियोजना की नियमित निगरानी करना, कृषि और सहकारिता विभाग एंवम परियोजना प्रबंधन इकाई के साथ समन्वय स्थापित करना और यदि कोई मुद्दे हो तो उन्हे कृषि और सहकारिता विभाग को अवगत करवाना।
2. राज्य अधिकार प्राप्त समिति का दो माह मे कम से कम एक बार मीटीग करना और राज्य में राष्ट्रीय ई--शासन योजना--कृषि के सफल कियान्वयन के लिए समग्र योजना, समन्वय, निगरानी, मूल्यांकन और मार्गदर्शन के लिए ज़िम्मेदार होना।
3. परियोजना के सुचारु एंवम शीघ्र कियान्वयन के लिए एक राज्य सृजित एजेंसी और एक राज्य मिशन लीडर को चुनना। मिशन लीडर सामान्य रुप से सचिव कृषि/आई0टी0 विभाग या प्रर्याप्त वरिष्ठता का कोई अन्य अधिकारी होना चाहिए।
4. जिला राष्ट्रीय ई--शासन योजना--कृषि कार्यान्वयन टीम (डी0एन0ए0आई0टी0) का गठन सुनिश्चित करना जिसका अध्यक्ष जिला कलैक्टर/मजिस्ट्रेट होगा जोकि जिला स्तर पर योजना के कियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।
5. हर विभाग द्वारा सूचना प्रोधौगिकी के उपकरणों की सूची सुनिश्चित करना, योजना के मानदण्डों के अनुसार आवश्यकताओं का आंकलन करना व वर्तमान सूचना प्रोद्योगिकी उपकरणों की सूची ध्यान में रखते हुए सूचना प्रोद्योगिकी प्रणाली का विभिन्न विभागों में वितरण सुनिश्चित करना।
6. राज्य कृषि पोर्टल के लिए आवश्यक अनुकूलन सलाह देना।
7. राज्य स्तर पर परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एन0आई0सी0 के साथ समन्वय बिठाना।
8. सेवाओं के 12 समूहों के इलावा अतिरिक्त सेवाओं को पहचानना।
9. परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित, बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों सहित आवश्यक सहायता प्रदान करना।

10. एजेंसी (एसडीए) नामित राज्य को प्रशासनिक सहायता प्रदान करें।

11. सभी विभागों में चिन्हित सेवाओं के लिए बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) को लागू करने में आवश्यक कानूनी बदलाव के लिए उचित कदम उठाना।

12. इस समिति को राज्य स्तरीय पी0 एम0 यू0 की मदद से कृषि या आई0टी0 विभाग द्वारा सेवित किया जाएगा।

13. कोई भी अन्य भूमिकाऐं या ज़िम्मेदारी जिसे राज्य सरकार उपयुक्त समझे।

वरिन्द्र सिंह कुण्डु
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

पृष्ठांकन कमांकः 5934–कृषि–II (1)–2015/1473 चण्डीगढ़ दिनांकः 05/02/16

एक प्रतिलिपि नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हरियाणा को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करने के लिए प्रेषित है।

अवर सचिव,
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग, हरियाणा।

पृष्ठांकन कमांकः 5934–कृषि–II (1)–2015/1474 चण्डीगढ़ दिनांकः 05/02/16

एक प्रतिलिपि सचिव कृषि, भारत सरकार, कृषि एवम किसान कल्याण मन्त्रालय, कृषि सहकारिता एवम किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को जानकारी के लिए प्रेषित है।

अवर सचिव,
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग, हरियाणा।

पृष्ठांकन कमांकः5934–कृषि–II (1)–2015/1475 चण्डीगढ़ दिनांकः 05/02/16

एक प्रतिलिपि निदेशक कृषि हरियाणा, पंचकुला को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित है। अनुरोध है कि इस अधिसूचना की प्रतिलिपियां वे अपने निजी स्तर पर सम्बन्धित विभागों को भिजवाने का कष्ट करें।

अवर सचिव,
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग, हरियाणा।